



भारत का अमृत महोत्सव
“भारत में क्लोनल वानिकी का विकास
(*Improvement of Clonal Forestry in India*)”
दिनांक 18.05.2021



भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को यादगार एवं विकासोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत सरकार एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के निर्देश पर अगस्त 2022 तक साप्ताहिक चलने वाले “भारत का अमृत महोत्सव” कार्यक्रम को समाजोपयोगी बनाने के लिये वन उत्पादकता संस्थान, रांची के निदेशक डा. नितिन कुलकर्णी के प्रतिबद्ध नेतृत्व एवं समूह समन्वयक अनुसंधान, डा. योगेश्वर मिश्रा के दिशानिर्देश में दिनांक 18.05.2021 को आभासीय मंच द्वारा “भारत में क्लोनल वानिकी का विकास (*Improvement of Clonal Forestry in India*)” विषय पर एक वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित किया गया जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी, शोधकर्मी सहित कुल 64 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम संचालिका श्रीमती रुबी सुसाना कुजुर ने निदेशक, समूह समन्वयक अनुसंधान/ व्याख्यान कर्ता एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संस्थान के निदेशक, डा. नितिन कुलकर्णी ने प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करते हुए माननीय प्रधानमंत्री की इस महत्वकांक्षी कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए देश की विकास में आजादी के महत्व पर विस्तार से चर्चा की एवं कार्यक्रम को समाजोपयोगी बनाने के लिये कार्यक्रम के विषय को एक वानिकी क्रांति बताया एवं ऐसे महत्वपूर्ण विषय चुनने के लिये डा. योगेश्वर मिश्रा की सराहना की तथा प्रतिभागियों को इसका भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय वानिकी में परिवर्तन, यूरोपीय देशों का इस क्षेत्र में काफी आगे होना, वानिकी का व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्लोनल वानिकी की अवधारणा, वानिकी के पारम्परिक तरीके एवं आधुनिक तरीकों की तुलना वानिकी में क्षेत्रीय कारक, उत्पादन/प्रतिफल में विलम्ब की समस्या आदि पर विस्तार से अपना विचार रखा एवं युवाओं से उनकी जानकारी सामने लाने का आग्रह किया।

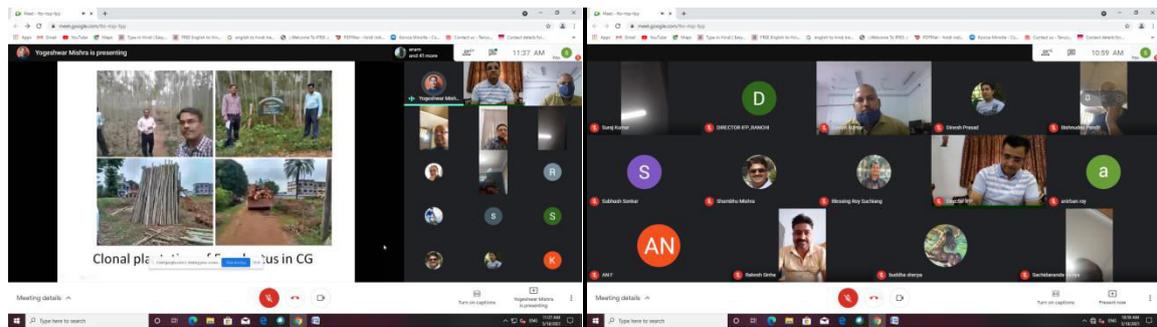
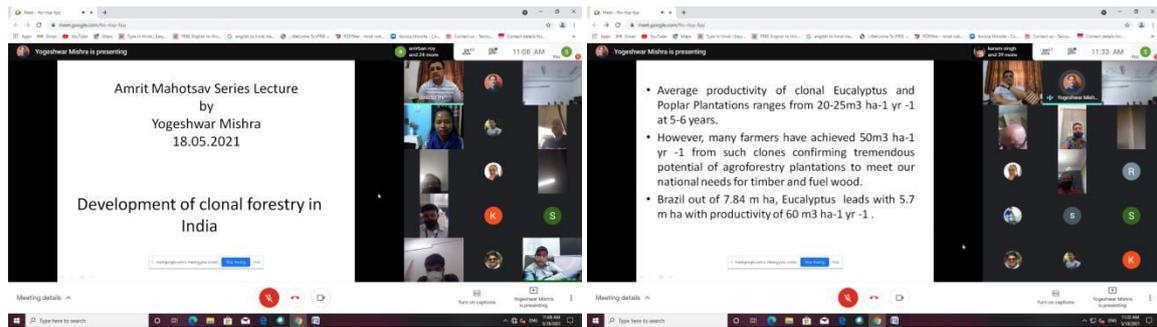
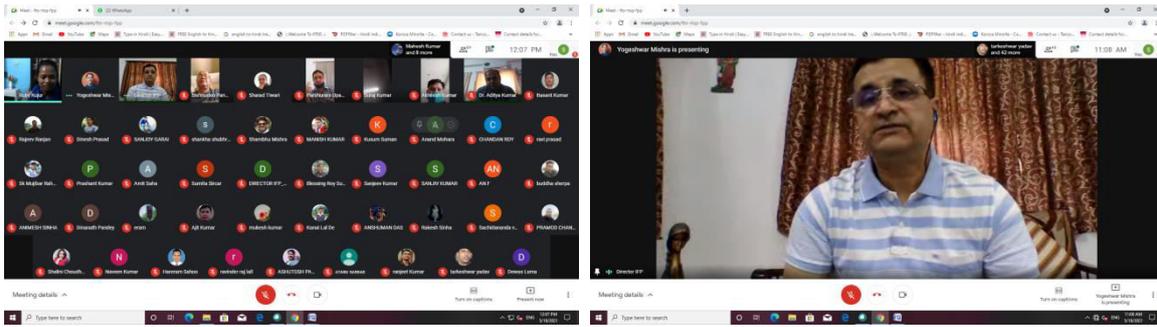
आज के कार्यक्रम के नायक एवं प्रस्तुतकर्ता डा. योगेश्वर मिश्रा ने स्वागतोपरान्त विषय प्रवेश करते हुए क्लोनल वानिकी के इतिहास चीन, ब्राजील, जर्मनी द्वारा क्लोन वानिकी के विकास एवं इसकी सफलता

तथा भारत का इस क्षेत्र में स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। मनचाही एवं सफल वानिकी के लिये क्लोनल वानिकी की आवश्यकता का तार्किक विश्लेषण करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक वानिकी में क्लोनल वानिकी के प्रति आम हितधारकों के झुकाव को रेखांकित किया। उन्होंने भारतीय वन अधिनियम 1865 से 1987 एवं पुनः 2014 में वर्णित दिशानिर्देशों को विस्तार से रखा। वानिकी के प्रकार (सामाजिक, कृषि, क्लोनल संरक्षण, संरक्षित, protection) आदि की चर्चा करते हुए निर्यात नीति, ब्रिटिश वन नीति का विस्तार, क्लोनल प्लांटिंग मटेरियल (clonal planting material) अधिनियम 1988, वृहद वनोत्पाद आदि का वर्णन विस्तार से किया। व्यापक अर्थ में $62\text{m}^3/\text{हे.}$ के मुकाबले भारत का $1\text{m}^3/\text{हे.}/\text{वर्ष}$ उत्पादन काफी कम है। बीज प्रमाणीकरण में NCCI की भूमिका, MSP बीज का स्रोत, उसकी गुणवत्ता आदि परेशानियों का भी जिक्र किया। कृषि वानिकी जमीन की उपलब्धता, ब्लांक पौधरोपण आदि को समझाते हुए क्लोनल वानिकी की विकास पर जोर दिया लेकिन सावधान किया कि खर्चीला होने के कारण सतर्क रहना आवश्यक है। युकलिप्टस, सुबबूल, पोपलर, केजुरीना आदि तीव्र बढ़वार वाले प्रजातियों की चर्चा करते हुए बताया कि वन उत्पादकता संस्थान भी पोपलर और मीलिया का क्लोन तैयार कर विस्तारित करने की स्थिति में है। युकलिप्टस के प्रति पानी शोषण की अवधारणा को खारिज करते हुए बताया कि इसका 785 लीटर/किलो बायोमास की अपेक्षा शीशम, धान, कपास क्रमशः 1322, 2000 एवं 3200 लीटर/किलो बायोमास पानी शोषित करता है। उन्होंने कुछ तीव्र बढ़वार वाले वानिकी प्रजाति का आर्थिक विश्लेषण भी किया। आइ.टी.सी. (ITC), भद्राचलन, जे.के. पेपर मील आदि के द्वारा क्लोनल रोपण सामग्री आपूर्ति का आंकड़ा बताते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, जर्मनी का रोपण क्षेत्र क्रमशः 18.4 मिलियन हे., 17.5 मिलियन हे., 11.2 मिलियन हे. तथा 7.8 मिलियन हे. की जगह भारत मात्र 4.1 मिलियन हे. में ही क्लोनल वानिकी कर पाया है। उन्होंने राज्य वन विभाग (State Forest Department) के सहयोग से इसपर विस्तार से कार्य करने का आह्वान किया। डा. अनिमेष सिन्हा, श्री संजीव कुमार, डा. शम्भुनाथ मिश्रा के सवालों का जवाब देते हुए उनकी आशंका को जायज बताया जबकि डा. आदित्य कुमार ने कुछ क्षेत्रों में क्लोनल वानिकी द्वारा कुछ समस्याओं का समाधान भी होने पर जोर दिया।

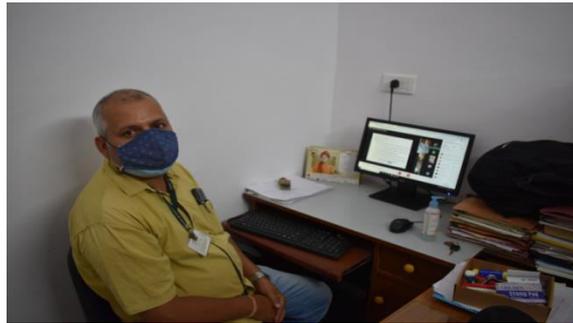
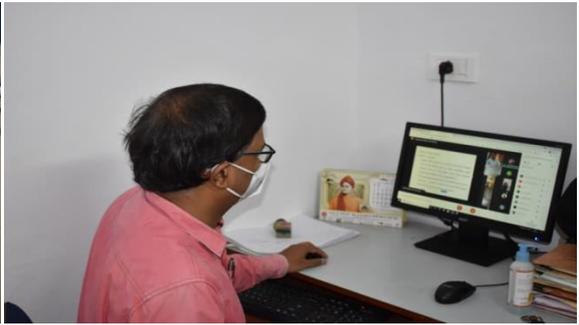
अंत में निदेशक महोदय ने कोविड-19 के माहौल को देखते हुए सतर्कता बरतने का आह्वान किया लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने की नसीहत भी दी। उन्होंने शोधार्थियों से आग्रह किया कि वो लोग आगे आएं और साप्ताहिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दें। एक क्षण भी बर्बाद किये बिना अपने शोध एवं सम्भावनाओं से राज्य सरकारें, संस्थानों एवं हितधारकों को अवगत कराए। वैज्ञानिकों से सेवा दर

प्रस्तावित करने का आग्रह करते हुए मोनो-कल्चर (mono-culture) से बचने तथा सरकार से परियोजना का समय विस्तार के लिए आग्रह का आश्वासन दिया।

श्रीमती रुबी सुसाना कुजुर ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विस्तार प्रभाग तथा सेवा एवं सुविधा विभाग की सहायनीय भूमिका रही।



कार्यक्रम की झलकियाँ



कार्यक्रम की झलकियाँ